

उद्योग से सम्बन्धित 25 नवम्बर 1969, के असाक्षित प्रश्न संख्या 1222 के उत्तर के सबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हा, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्रवचयाम्म ओका) (क) जी हैं,

(ख) यह सब है कि गढ़वाल के वनों की इमारती लकड़ी को इस क्षेत्र की नदियों से बहाया जाता है और उन रथानों पर पहुँचाया जाता है जहाँ इसका बाजार है। जहाँ तक गढ़वाल में इमारती लकड़ी पर आधारित उद्योगों की स्थापना का प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा समस्त पर्वतीय क्षेत्र का सर्वेक्षण करवाया था। रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ गढ़वाल में इमारती लकड़ी पर आधारित कुछ उद्योगों की स्थापना करने की सिफारिश की गई थी, उत्तर प्रदेश सरकार के विचाराधीन है। राज्य सरकार पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए उत्सुक है और उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के लिए एक पर्वतीय विकास बोर्ड की स्थापना कर दी है। यह बोर्ड गढ़वाल सहित पर्वतीय जिलों में गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्योगों के प्रकार के बारे में सिफारिश करेगा।

अलकनन्दा में बाढ़ आने के कारण हुई सम्पत्ति की हानि तथा सरकार द्वारा की गई वित्तीय सहायता

147. श्री प्रतप सिंह नेगी क्या सिचाई और बिज्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :  
(क) जुलाई, 1970 में अलकनन्दा में

श्रीमती विनयाशकारी बाढ़ के परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों की सम्पत्ति तथा भूमि क्षतिग्रस्त हुई है ?

(ख) उपयुक्त क्षेत्रों में जिन व्यक्तियों की सम्पत्ति तथा भूमि क्षतिग्रस्त हुई है उन्हें कितनी सहायता देने का विचार है;

(ग) इन व्यक्तियों को सरकार द्वारा यह सहायता दिये जाने का निश्चय करने में कितना समय लगेगा, और

(घ) उपयुक्त बाढ़ के कारण प्रदूषित इत्र जाँच समिति के प्रतिवेदन का व्यौरा क्या है ?

सिचाई और बिज्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री नृजनय कुरील) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई, 1970 में अलकनन्दा की बाढ़ों के फलस्वरूप उन व्यक्तियों को संख्या, जिनकी सम्पत्ति और भूमि को क्षति पहुँची है, 11,610 हैं।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों को 1,49,100 रुपये की धनराशि पहले ही वित्तीय सहायता के रूप में दे दी है।

(घ) अलकनन्दा में बाढ़ों की जाँच करने के लिए न तो केन्द्रीय सरकार ने और न ही राज्य सरकार ने ही कोई समिति स्थापित की है। बहरहाल, सिचाई और बिज्युत मंत्रालय ने जुलाई, 1970 की बाढ़ों के दौरान गंगा नहर में गाढ़ भरने के कारणों का प्रश्न ख्याते के लिए एक समिति बनाई है। समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

Applications received from Tamil Nadu for Industrial Licences

148. SHRI S. A. MURUGANATHAM :  
Will the MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(AUDYOGIK VIKAS MANTRI) be pleased to state :

(a) the number of applications for licences for new industrial units forwarded by the Tamil Nadu Government to the Centre in the last three years;

(b) the number of applications sanctioned; and

(c) the number of applications rejected and the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (AUDYOGIK VIKAS MANTARALAYA MEN RAJYA MANTRI) (SHRI GHANSHYAM OZA) : (a) The applications for industrial licences are normally received from the parties direct. During the period from 1st January, 1968 to 31st December 1970, 132 applications were received for the grant of industrial licences for the establishment of new industrial Undertakings in Tamil Nadu.

(b) 2 Industrial licences and 34 letters of intent have so far been issued.

(c) 46 applications have so far been rejected. The reasons for rejection were that there was no scope for creating additional capacity, the industry was reserved for development in the Small Scale sector etc.

#### Recommendations of Committee on Power Economy

149. SHRI NIHAR LASKAR :  
SHRI S. M. KRISHNA :  
SHRI M. KATHAMUTHU :

Will the MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (SINCHAI AUR VIDYUT MANTRI) be pleased to state :

(a) whether Government have received the Report of the Committee on Power Economy which was appointed by Government;

(b) if so, what are its recommendations; and

(c) how for these recommendations have been accepted by Government ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SINCHAI AUR VIDYUT MANTRALAYA MEN UP-MANTRI) (SHRI B. N. KUREEL) : (a) Yes, Sir.

(b) The Power Economy Committee has made 188 recommendations and conclusions in all pertaining to :—

1. the pattern of utilisation of available plant capacity, their operational efficiency and the scope of improving economy in power generation;
2. the economics of power generation from different sources viz., hydro, thermal and nuclear under prevailing conditions;
3. the conditions of power supply including reliability, voltage fluctuations and transmission losses;
4. the causes of delay in the execution of power projects and the measures for improving the manner of implementation of power projects and reducing construction periods;
5. technical and economical aspects of rural electrification.

(c) The recommendations of the Committee are under consideration of the Government.

#### Report of Commission on Car Prices

150. SHRI NIHAR LASKAR :  
SHRI P. GANGADEB :  
SHRI M.M. JOSEPH :

Will the MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (AUDYOGIK VIKAS MANTRI) be pleased to state :